(ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुबंध–II में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची दी गई है।

(ग) वर्ष 1993–94 के आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद शुल्क में छूट अथवा रेल भाड़े में छूट अथवा महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों के लिए कोई अन्य वित्तीय छूट देने के प्रस्तावों के बारे में इस अवस्था में सरकार की स्थिति का उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

(घ) सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय मशीकरण निधि का उद्देश्य कोर क्षेत्र के उद्योगों सहित अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है जो औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित हो सकते हैं।

Underpricing of Shares of Neyveli Lignite Corporation

1717. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Public Enterprises underpriced the shares of the Neyveli Lignite Corporation at a rate of Rs. 17/-; and that the prices of shares shot up from Rs. 17 to Rs. 60—80 soon after the allotment thereof;

(b) if so, what are the reasons for underpricing of shares indicating the methodology was adopted in this case and the authority which tendered advice for fixing the price; and

(c) whether the Companies which purchased the shares of Neyveli Lignite Corporation at the rate of Rs. 17/- per share subsequently disposed of the same in public; if so, at what rate and quantum of such shares sold ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) In October, 1992, Government offered 5% of the shares of NLC for sale and sold 1.04% of the shares at an average price of Rs. 23.40 per share. Government fixed the referal price of NLC shares @ Rs. 17/- per share based on the advice of the three major merchant bankers, viz., Industrial Credit and Investment Corpn. of India, Industrial Development Bank of India and SBI Capital Markets Ltd.

In October the NLC shares were quoted between Rs. 16 and Rs. 20 in the Madras Stock Exchange in some sporadic trading. The shares of NLC have since been traded in Stock Exchange very sporadically. No conclusion can or should be drawn based on a very limited trading as to under or overpricing of the shares.

The purchaser is free to off-load the shareholdings through the normal Stock Exchange trancactions.

1718. [*Transferred to 8th December*, 1992].

औद्योगिक विकास दर में गिरावट

1719. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1992 को "आब्जर्वर" में "वरिड बाइ स्लम्प इन इनडस्ट्री" पी॰ एम॰ ओ॰ कालस स्पेशल मीट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर निर्धारित लक्ष्य से कम होने की आशंका है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्य के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) से (ग) औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के संबंध में अंतर्मंत्रालयीय संचालन समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार वार्षिक आधार पर औद्योगिक विकास दर के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, जुलाई, 1992 की अवधि तक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई, 1992 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विकास दर में (+) 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

Discontinuance of reservation for S.S.I.

1720. SHRIMATI KAMLA SINHA :
DR. BAPU KALDATE :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to discontinue reservations for the Small Scale Industries in the country;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what are the implications involved in so far as the economic viability of the small scale industries are concerned as a consequence thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO & RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN) : (a) to (c) There is no proposal with the Government for discontinuance of the reservations for small scale industrial sector. In the Industrial Policy announced on 24th July, 1991 it has been stated that the reservation policy would continue.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

1721. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 तक देश में सरकारी क्षेत्र के कुल कितने उपक्रम कार्यरत थे;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ उपक्रम गत तीन वर्षों से निरंतर घाटे में चल रहे थे;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनमें मार्च, 1992 तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया था;

(घ) शेष उपक्रमों में मार्च, 1992 तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ब्याज की वर्ष-वार औसतन राशि कितनी-कितनी थी; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों द्वारा अर्जित वर्षवार औसतन लाभ की राशि कितनी-कितनी थी ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (च) वांछित सूचना लोक उद्यम सर्वेक्षण 1991-92 में शामिल की जाएगी जिसे तैयार किया जा रहा है और आशा है कि इसे अगले बजट अधिवेशन के दौरान संसद के दोनों सदनों के सामने रख दिया जाएगा।

ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिये योजना

1722. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार